पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI) 2026 (GS पेपर III – पर्यावरण)

चर्चा में क्यों?

- येल (Yale) पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI) 2026 में भारत को 177 देशों में से 176वाँ स्थान मिला है, जिसका स्कोर 22.46 है, जो विश्व में दूसरा सबसे निम्न (लाओस के ऊपर) है।
- एस्टोनिया (Estonia) शीर्ष पर रहा, जिसका स्कोर 74.79 है।

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI) – परिचय

- यह एक द्विवार्षिक (हर दो वर्ष में) वैश्विक पर्यावरण मूल्यांकन सूचकांक है।
- प्रारंभ: 2000
- प्रकाशितकर्ता:
  - येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल लॉ एंड पॉलिसी (YCELP)
  - सेंटर फॉर ईंटरनेशनल अर्थ साईस ईफॉर्मेशन नेटवर्क (CIESIN), कोलंबिया विश्वबितालय
- उद्देश्य: वैज्ञानिक और डेटा-आधारित संकेतकों का उपयोग करके देशों के पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करना।

EPI 2026 की रूपरेखा

- 177 देश
- 47 संकेतक
- 12 पर्यावरणीय मूद्धा श्रेणियाँ
- 3 नीति उद्देश्य:
  1. पर्यावरणीय स्वास्थ्य
  2. पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंतता
  3. जलवायु परिवर्तन

महत्व

- यह निम्नलिखित लक्ष्यों की दिशा में देशों की प्रगति पर नज़र रखता है:
  - → सतत विकास लक्ष्य (SDGs)
  - → पेरिस समझौता (Paris Agreement)
  - → कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा

भारत का प्रदर्शन

वर्ष	2022	2024	2026
स्थान	180	176	176

- भारत वर्ष 2022 से लगातार पाँच सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल रहा है।

EPI पद्धति पर सरकार की आलोचना

भारत की राय (MoEFCC)

- यह सूचकांक –
  - भारत के विकास स्तर और गरीबी उन्मूलन प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करता है।
  - जनसंख्या के आकार को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाता।
  - ऐतिहासिक उत्सर्जन (Historical Emissions) की अनदेखी करता है।
  - समान लेकिन भिन्न दायित्व (CBDR) के सिद्धांत को अनदेखा करता है।
  - अनुमानित (extrapolated) आँकड़ों और सरल देशों के बीच तुलना पर आधारित है।

येल का जवाब

- EPI वर्तमान पर्यावरणीय परिणामों का मूल्यांकन करता है, भविष्य के नीति वचनों का नहीं।
- इसका उद्देश्य वर्तमान नीतिगत निर्णयों को मार्गदर्शन देना है, न कि ऐतिहासिक जिम्मेदारी तय करना।

प्रमुख सरकारी पहलें

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)
- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC)
- स्वच्छ भारत मिशन
- मिशन LiFE (Lifestyle for Environment)
- नमामि गंगे कार्यक्रम
- ग्रीन इंडिया मिशन
- राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना
- CAMPA फंड
- जल जीवन मिशन
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी)

अंतरराष्ट्रीय ढाँचे (संबंधित)

- पेरिस समझौता (2015)
- सतत विकास लक्ष्य (SDGs 6, 11, 12, 13, 14 एवं 15)
- जैव विविधता पर सम्मेलन (CBD)
- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा (2022)
- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)
- रामसर कन्वेंशन (आर्द्रभूमि संरक्षण)
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एवं किगाली संशोधन
- संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक (2021-2030)

सुधार के क्षेत्र

① जलवायु परिवर्तन (रैंक: 130)

- पिछले दशक में स्कोर में 13.98 अंकों की सुधार हुआ।
- सुधार के कारण:
  - नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार
  - ऊर्जा दक्षता में सुधार
  - जलवायु-संबंधी नीतियों और विनियमों को सुदृढ़ करना

② अपशिष्ट प्रबंधन (रैंक: 141)

- नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार।
- स्वच्छ भारत मिशन का सकारात्मक प्रभाव।

③ स्वच्छता (रैंक: 141)

- शौचालय कवरेज का विस्तार।
- स्वच्छता अवसंरचना में सुधार।

चिंताजनक प्रमुख क्षेत्र

① वायु गुणवत्ता (रैंक: 174)

मुख्य स्रोत

- वाहनों से उत्सर्जन
- कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र
- औद्योगिक प्रदूषण
- निर्माण कार्यों से धूल
- बायोमास जलाना

② जैव विविधता (रैंक: 174)

- आवास विनाश
- वनों की कटाई
- अवसंरचना विस्तार
- पारिस्थितिकी तंत्र का विखंडन

अन्य चिंताएँ

- वृक्ष आच्छादन में गिरावट
- अस्थायी एवं असतत मछली पालन
- उच्च कीटनाशक प्रदूषण
- अपर्याप्त शहरी अपशिष्ट जल उपचार
- कई शहरों में प्रदूषण नियंत्रण की कमजोरी

भारत के लिए प्रमुख चुनौती

- क्षार्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना।
- तीव्र शहरीकरण और औद्योगिकीकरण से पर्यावरणीय दबाव लगातार बढ़ रहा है।

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 48A: पर्यावरण के संरक्षण और सुधार का प्रावधान।
- अनुच्छेद 51A(g): प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है।

आगे की राह (Way Forward)

- ✓ पर्यावरणीय कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को मजबूत करना।
- ✓ स्वच्छ परिवहन और कड़े औद्योगिक उत्सर्जन मानकों के माध्यम से शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार करना।
- ✓ नवीकरणीय ऊर्जा को तेजी से अपनाना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना।
- ✓ अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों और समेकित अपशिष्ट प्रबंधन का विस्तार करना।
- ✓ टिकाऊ कृषि और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना तथा कीटनाशक उपयोग कम करना।
- ✓ वनीकरण, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन और जैव विविधता संरक्षण गतिविधियों को बढ़ाना।
- ✓ पर्यावरणीय आँकड़ों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और परिणाम-आधारित निगरानी को बेहतर बनाना।
- ✓ विकास योजनाओं में पर्यावरणीय स्थिरता को एकीकृत कर समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करना।

Environmental Performance Index (EPI) 2026 (GS Paper III – Environment)

Why in News?

- Yale Environmental Performance Index (EPI) 2026 ranked India 176th out of 177 countries with a score of 22.46, making it the second-lowest globally (above Laos).
- Estonia topped the index with a score of 74.79.

Environmental Performance Index (EPI)

About

- A biennial global environmental assessment index.
- Launched: 2000.
- Published by:
  - Yale Center for Environmental Law & Policy (YCELP)
  - Center for International Earth Science Information Network (CIESIN), Columbia University.
- Objective: Evaluates countries' environmental performance using scientific, data-driven indicators.

EPI 2026 Framework

- 177 countries
- 47 indicators
- 12 environmental issue categories
- 3 Policy Objectives:
  1. Environmental Health
  2. Ecosystem Vitality
  3. Climate Change

Significance

Tracks countries' progress towards:

→ Sustainable Development Goals (SDGs)
→ Paris Agreement
→ Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework

India's Performance

Year	2022	2024	2026
Rank	180	176	176

- India has remained among the five worst-performing countries since 2022.

Criticism of EPI Methodology

India's View (MoEFCC)

The index:

- Ignores India's development stage and poverty reduction priorities.
- Does not adequately account for population size.
- Overlooks historical emissions.
- Ignores the principle of Common but Differentiated Responsibilities (CBDR).
- Relies on extrapolated data and simplified cross-country comparisons.

Yale's Response

- EPI evaluates current environmental outcomes, not future policy commitments.
- It is intended to guide present-day policymaking rather than assign historical responsibility.

Areas of Improvement

① Climate Change (Rank: 130)

- Score improved by 13.98 points over the last decade.
- Progress driven by:
  - Expansion of renewable energy.
  - Improved energy efficiency.
  - Stronger climate-related regulations.

② Waste Management (Rank: 141)

- Better municipal solid waste management.
- Positive impact of Swachh Bharat Mission.

③ Sanitation (Rank: 141)

- Expansion of toilet coverage.
- Improved sanitation infrastructure.

Major Areas of Concern

① Air Quality (Rank: 174)

Major Sources

- Vehicular emissions
- Coal-based thermal power plants
- Biomass burning
- Industrial pollution
- Construction dust

② Biodiversity (Rank: 174)

- Habitat destruction
- Deforestation
- Infrastructure expansion
- Ecosystem fragmentation

Other Concerns

- Declining tree cover
- Unsustainable fisheries
- High pesticide pollution
- Inadequate urban wastewater treatment
- Weak pollution control in cities

Key Challenge for India

Balancing:

→ Economic development.
→ Energy security.
→ Environmental sustainability.

Rapid urbanisation and industrialisation continue to intensify environmental pressures.

Constitutional Provisions

- Article 48A : Protection and improvement of the environment.
- Article 51A(g): Fundamental duty to protect and improve the natural environment.

Way Forward

✓ Strengthen enforcement of environmental laws.
✓ Improve urban air quality through cleaner transport and stricter industrial emission standards.
✓ Accelerate renewable energy adoption and reduce fossil fuel dependence.
✓ Expand wastewater treatment and integrated waste management.
✓ Promote sustainable agriculture and natural farming to reduce pesticide use.
✓ Increase afforestation, ecosystem restoration and biodiversity conservation.
✓ Improve environmental data quality, transparency and outcome-based monitoring.
✓ Integrate environmental sustainability into development planning for inclusive and sustainable growth.